an>

Title: Regarding crop loss suffered by the farmers of Western Uttar Pradesh due to hailstorm.

**श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) :** अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की जो दुर्दशा हुई है, उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार यहां रखे हैं। हम फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, लेकिन किसानों की जो जिंदगी गई है, जो ह्यूमन लाइफ की बात करें तो उसका रुपयों में आकलन लगाना सम्भव नहीं है। किसान का जीवन अमूल्य है, प्राइसलैस है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गंदा मज़ाक किया जा रहा है, वहां के किसानों के साथ, सर्वे के नाम पर लेखपाल गांव में जाता है। रूलिंग पार्टी के किसी सदस्य के पास बैठता है। उससे दस नाम लिखवा लेता है। खेतों में वह नहीं जाता है, किसी प्रकार का सर्वे नहीं करता है। उन दस लोगों के नाम के आठ-आठ और दस-दस हजार रुपये के चैक बन कर आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की फसल वास्तव में नष्ट हुई है, उनको एक रुपया तक नहीं मिलता है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद सहारनपुर में अभी तक 19 मौतें इस कारण से हो चुकी हैं। जिनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या की है और कुछ लोगों की तनाव के कारण मौत हुई है। प्रशासन का यह कहना है कि ये लोग ओलावृष्टि के कारण नहीं मरे हैं, बल्कि नेचुरल कॉज़िस की वजह से मरे हैं। मैं मुंडी खेड़ी गांव के एक किसान राजपाल जी के बारे में बताना चाहता हूं कि जब उसके पास तहसील का अमीन रिकवरी करने के लिए आया, जिसके बाद वह किसान अपने खेत में गया। उसने वहां देखा कि कैसे उसकी फसल बर्बाद पड़ी है। वह घर वापस आया और उसने माथे पर दोनों हाथ रखे और वहीं दम तोड़ दिया। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार से उस किसान की मृत्यु का मज़ाक उड़ाना चाहती है?

मेरा आपके माध्यम से अपनी सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ यह जो अन्याय हो रहा है और जिस प्रकार से गेहुं की फसल 75 से 80 प्रतिशत नष्ट हो चुकी है। जो फसल गिरी हुई है, वह तो खराब है ही, लेकिन जो खड़ी है, वह भी खराब है, उसका सही सर्वे करवा कर, सही आकलन करवा कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जिन किसानों ने ओलावृष्टि और आपदा के कारण अपना जीवन खो दिया है, अपने प्राण खो दिए हैं, उन किसानों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देशित करे कि वह सर्वे सही रूप से करे।